Amendments in Finalised Version of GATT Treaty

4325. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI G. G. SWELL :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether any amendments has been done at Morocco on GATT Treaty in its finalised version in December, 1993 and if so, details thereof ;

(b) the countries that supported and opposed USA on the issue of social and labour standards at GATT ;

(c) whether Government's attention has been drawn to the observation made by US trade official and reported in "Observer" of 7th April, 1994 that under the rules of the GATT, objection by even one country is enough to block discussion on any issue or any fresh issue and if so, details thereof ; and

(d) what are the detailed positive and negative aspects in terms of benefits or losses to India due to GATT ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) No, Sir.

(b) The major countries pleading for the inclusion of the consideration of the relationship between international trade and internationally recognized workers rights were the U.S, the EC and the Nordic countries. Almost all developing countries and Canada were not in favour of this subject being considered by the WTO.

(c) The Ministerial decision establishing the Preparatory Committee lays down that all decisions of the Prep. Com. will be on the basis of consensus.

(d) The Uruguay Round results will establish a rule-based multilateral trading system with expanded coverage. This will on the whole be advantageous to us in increasing our exports. There will be increased market access opportunities for Indian goods as a result of lowering of tariffs and the phase out of the Multi Fibre Arrangement. The Services Agreement would also provide export opportunities. The rules governing the multilateral trading system have been strengthened. Though we will be required to amend our patents regime, there are safeguards in the Agreement against the abuse of patent rights by the right holder The use of price control measures is also not prohibited. We have flexibility to devise our own sui generis system of plant variety protection with provisions for farmers and researchers rights. In the area of agriculture, our development and public welfare policies will not be constrained.

वर्ष 1993-94 के दौरान आयात और निर्यात

4326. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी धन राशि का आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धन राशि का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल-फरवरी, 1993-94, वह अद्यतनिकतम अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध है, के दौरान भारत के आयात और निर्यातो का मूल्य निम्नलिखित है :—

	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
आयात (अनन्तिम)	63780.43	20335.03
निर्यात (अनन्तिम)	62181.31	19825.19

कोयले का आयात

4327. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विदेशों से कोयले का आयात कर रही है अथवा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितनी-कितनी मात्रा में तथा किस प्रकार के कोयले का आयात किया जा रहा है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या विदेशों से कोयला आयात करने का निर्णय किसी दबाव के तहत लिया गया है और क्या

इस संबंध में किन्हीं शर्तों का अनुपालन भी किया जा रहा है;

(घ) क्या विदेशों से आयात किया जाने वाला कोयला भारत में उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोयला आयात करने के क्या कारण हैं और घरेलू कोयला बाजार पर कोयले के आयात का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) उदारीकृत निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अन्तर्गत सभी लोगों को कोयले का बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है । मुक्त रूप आयात किए जाने की अनुमति को देखते हुए मूल्य, मात्रा तथा क्वालिटी और आयात-स्रोत की दृष्टि से कोयले के संभावित आयात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(घ) तथा (ङ) धुले हुए कोकिंग कोयले का स्वदेशी उत्पादन देश के इस्पात संयंत्रों की स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए, मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पाटने के लिए मिश्रण प्रयोजन हेतु कम राख वाले कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है ।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की प्रभाविता

4328. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1994 के दैनिक "पायनियर" में "हाऊ एफेक्टिव आर०ई०पी०जेड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कुछ वर्षों से निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे निर्यात के मूल्य की प्रतिशतता में देश के कुल निर्यात मूल्य के संदर्भ में निरंतर कमी आ रही है;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में देश से होने वाले कुल निर्यात मूल्य का कितना प्रतिशत इन शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया गया है;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा आयात भी किया गया है; यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में इन इकाइयों द्वारा वर्ष-वार कितने-कितने मूल्य का आयात किया गया; और

(ङ) क्या सरकार ने इन औद्योगिक इकाइयों के कार्यकरण की समीक्षा की है; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) पूर्ववर्ती सोवियत संघ में बाजार अव्यवस्था के कारण वर्ष 1992-93 में आई एक छोटी-सी गिरावट को छोड़कर निर्यात प्रोसेसिंग जोनों से किये गये निर्यात में राष्ट्रीय निर्यात की तरह तीव्र वृद्धि रही है जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट हैं :—

वर्ष	देश के निर्यात का कुल मूल्य (करोड़ रु०)	निर्यात प्रोसेसिंग जोनों के कुल निर्यात का मूल्य	प्रतिशतता
1991-92	44042	1177	2.67
1992-93	53686	1376	2.56
1993-94 (फरवरी, 1994 तक)	62181	1641	2.64

(घ) जी, हां । निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में स्थित एककों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए आयात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयात मूल्य (करोड़ रु०)
1991-92	751.55
1992-93	936.51
1993-94 (अनन्तिम)	1349.71

(ङ) व्यापारियों और उद्योगियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर इस योजना के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं ।

Non-product and product specific subsidies on agriculture

4329. SHRI BHUPENDER SINGH MANN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what are the figures about non-product specific subsidies and product specific subsidies on agriculture during the last three years ; and